डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन दिनांक 1 अक्टूबर, 2024, डिस्पेच दिनांक 1 अक्टूबर, 2024

| वर्ष 68 | अंक 09 | भोपाल | 1 अक्टूबर, 2024 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के शुरूआती 100 दिनों में सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन

श्री अमित शाह ने 2 लाख नए PACS, प्राथमिक डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन एवं सुदृढ़ीकरण' पर मार्गदर्शिका' के साथ, श्वेत क्रांति 2.0 और 'सहकारिता में सहकार' पर मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किया

श्वेत क्रांति 2.0 महिला स्वावलंबन और सशक्तीकरण के साथ-साथ कुपोषण के खिलाफ जंग को भी ताकत देगी

मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों में ली गई 10 पहलें सहकारिता क्षेत्र को आत्मनिर्भर व व्यापक बनाने का काम करेंगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के संकल्प को पशुपालन के व्यवसाय से और मजबूत होगी

डेयरी से जुड़ी कोई भी मशीनरी अब विदेशों से लाने की जरूरत नहीं, इनका शत प्रतिशत उत्पादन भारत में होगा

दो लाख प्राथमिक सहकारी समितियां रजिस्टर होते ही देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां PACS, डेयरी या मत्स्य सहकारी समिति ना हो

PACS को 25 अलग-अलग कामों से जोड़ कर इन्हें viable किया जा रहा है

ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के लिए डेयरी क्षेत्र सबसे उपयुक्त माध्यम है

डेयरी के जरिये अब विदेशी मुद्रा का अर्जन भी किया जा सकेगा

हर व्यक्ति की अच्छाइयों को एकत्रित कर राष्ट्र के विकास में लगाना ही सहकारिता का लक्ष्य है

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के शुरूआती 100 दिनों में सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की I इस अवसर पर केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी और पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ़ श्री ललन सिंह, सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल और सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे I इस दौरान श्री अमित शाह ने ने 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), प्राथमिक डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन एवं सुदृढ़ीकरण' पर मार्गदर्शिका' के साथ, श्वेत क्रांति 2.0 और 'सहकारिता में सहकार' (Cooperation Among Cooperatives) पर मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किया।

राष्ट्रीय सम्मलेन को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे टर्म के 100 दिनों में सहकारिता मंत्रालय ने 10 महत्त्वपूर्ण पहल की है, उनमें से आज तीन पहलों को लॉन्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्षों से मांग की जा रही थी कि देश के 15 से अधिक क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की गतिविधियों से जुड़े सहकारिता आंदोलन को समग्र अप्रोच और समान विकास की दृष्टि से देश के हर गाँव तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्रालय का गठन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लगभग 70 सालों तक यह मांग सत्ता के गलियारों में इधर-उधर घूमती रही, लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्वतंत्र स्थापना का निर्णय लिया। श्री शाह ने कहा कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि मोदी जी ने उन्हें देश का पहला सहकारिता मंत्री बनने का सम्मान दिया।

श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता वह शक्ति है जो व्यक्ति की शक्तियों को सामूहिक रूप से लाकर समाज की शक्ति के रूप में परिवर्तित कर देती है। उन्होंने कहा कि सहकारिता का मंत्र यही है कि सब साथ आएं, सबकी अच्छाइयां एकत्रित हों, किसी की कमी दिखाई नहीं दे और सभी की अच्छाइयां राष्ट्र के विकास में सहायक बनें। उन्होंने कहा कि सहकारिता के मंत्र ने कई जगह पर चमत्कारिक परिणाम दिखाए हैं, लेकिन पिछले काफी समय से हमारे देश में सहकारिता आंदोलन अप्रासंगिक बनता जा रहा था। श्री शाह ने कहा कि बीते 70 साल में सहकारिता आंदोलन के मूल तत्व को सहेज कर सहकारिता में जो आवश्यक परिवर्तन करने थे, वह नहीं किए गए जिसके कारण कुछ राज्यों में सहकारिता काफी सफल हुई, कुछ में राज्य सरकार की दया पर निर्भर हो गई और कुछ राज्यों से लुप्त ही हो गई।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि जब सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया तो उद्देश्य यह था कि देश के हर जिले और गाँव में सहकारिता पुनर्जीवित हो, सहकारिता के क़ानून एवं इसकी कार्य-प्रणालियों और संस्कृतियों को समय अनुकूल बनाकर नए सांचे में ढाला जाए, ताकि इससे 140 करोड़ की आबादी वाले देश में रोजगार प्रदान करने की एक नई शुरुआत हो और न केवल देश संपन्न बने, बल्कि हर व्यक्ति स्वाभिमान के साथ अपना जीवन-यापन कर पाए। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को लेकर पिछले तीन साल में काफी काम हुए, जिसके तहत अब तक 60 से अधिक नई पहल की गई है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 100 दिनों में जो 10 पहल की गई है, वे सभी पहल सहकारिता क्षेत्र को परिपूर्ण बनाने में बहुत बड़ा योगदान देंगी। उन्होंने कहा कि इनमें दो लाख, प्राथमिक डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियां और PACS, इन तीनों का एक संयुक्त प्रस्ताव बनाकर हमने देशभर में भेजा था। देश की सभी राज्य सरकारों ने इसे स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि दो लाख प्राथमिक सहकारी समितियां रजिस्टर होते ही देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां PACS, डेयरी या मत्स्य सहकारी समिति ना हो।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

दुग्ध संघ की उत्पादन क्षमता बढ़ायी जाएगी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

10 लाख टन तक पहुंचाया जायेगा उज्जैन दुग्ध संघ का उत्पादन

प्रत्येक किसान परिवार को 50 हजार रु. बोनस पहुंचे यह सुनिश्चित करेंगे

मुख्यमंत्री उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के कर्मचारी संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। शासन का प्रयास है कि दुग्ध संघ के माध्यम से दुग्ध उत्पादक किसान अधिकाधिक रूप से लाभान्वित हों। प्रत्येक किसान परिवार के पास कम से कम 50 हजार रुपए बोनस राशि पहुंचे। उज्जैन दुग्ध संघ की उत्पादन क्षमता को 10 लाख टन तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही दुग्ध संघ की भूमिका को धरातल स्तर तक प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव उज्जैन में रविवार को सहकारी दुग्ध संघ के कर्मचारी संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कृषि आधारित मध्यप्रदेश में किसानों की आय में और अधिक वृद्धि हो इसके लिए शासन कृत-संकल्पित है। प्रदेश की कृषि विकास दर को और आगे ले जाना है। इसमें पशुपालक दुग्ध उत्पादक किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शासन का प्रयास है कि दुग्ध उत्पादन में और अधिक वृद्धि हो। इसमें दुग्ध सहकारिता की बड़ी भूमिका रहेगी। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के साथ बढ़ी हुई मात्रा की खपत के लिये भी कार्य किया जाएगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से दुग्ध खपत के लिये दुग्ध संघ की क्षमता में वृद्धि की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दुग्ध सहकारी संघ को मजबूत बनाने के साथ किसानों के लिए जितनी भी राशि चाहिए वह दी जाएगी। धरातल स्तर तक दुग्ध सहकारी संघ की भूमिका को प्रभावी बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन दुग्ध संघ मेरा अपना परिवार है। वर्तमान में उज्जैन दुग्ध संघ की ढाई लाख टन की क्षमता में वृद्धि कर 10 लाख टन तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके प्रॉफिट को भी बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए तक ले जाना है। साथ ही कर्मचारी हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।

कार्यक्रम में विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, जनप्रतिनिधि, दुग्ध संघ से जुडे पदाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

लघु वनोपज के संग्रहण के लिए प्रदेश में 126 वन-धन विकास केन्द्र बने

भोपाल : प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय बहुल 20 जिलों में 126 वन-धन विकास केंद्र निर्मित किये जा चुके हैं। इन केन्द्रों में वर्तमान में करीब 37 हजार 800 से अधिक सदस्य पंजीकृत हैं। वन-धन विकास केन्द्रों के जरिये लघु वनोपजों का सतत् रूप से संग्रहण, प्राथमिक स्तर का प्र-संस्करण एवं विपणन तथा बाजार की मांग एवं उपलब्धता के आधार पर इन लघु वनोपजों का मूल्य संवर्धन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वनोपज संग्रहण का कार्य मुख्यत: प्रदेश में निवासरत जनजातीय समुदाय द्वारा ही किया जाता है।

प्रदेश में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना (पीएम जन-मन) में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के लिए कुल 198 वन-धन विकास केंद्र बनाये जाने हैं। इसके लिए प्रदेश के 24 पीवीटीजी बहुल जिलों में से 17 जिला लघु वनोपज यूनियन में अनूपपुर, अशोकनगर, उत्तर बालाघाट, दक्षिण बालाघाट, पूर्व छिंदवाडा, पश्चिम छिंदवाडा, दक्षिण छिंदवाड़ा, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, कटनी, पूर्व मंडला, पश्चिम मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, दक्षिण शहडोल, श्योपुर, सीधी, शिवपुरी, रायसेन एवं विदिशा को चिन्हित किया गया है। वर्तमान में इन जिलों से करीब 1 करोड़ 47 लाख 65 हजार रूपये की लागत से बनने वाले 221 (लक्ष्य 198 से भी अधिक) पीवीटीजी वन-धन विकास केंद्रों के निर्माण प्रस्ताव भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन एवं विकास संघ लिमिटेड (ट्राईफेड) नई दिल्ली एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं। इसमें से ट्राईफेड द्वारा 57 पीवीटीजी वन-धन विकास केंद्र इसी साल जनवरी में ही मंजूर कर दिये गये हैं।

"क्या है योजना"

वनोपजों के जरिये जनजातीय समुदायों की आय बढ़ाने और इन्हें वनोपज विक्रय के मुनाफे का अधिकतम लाभ दिलाने के लिये भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री वन-धन विकास योजना प्रारंभ की थी। इस योजना का क्रियान्वयन म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में पीएम वन-धन विकास योजना का क्रियान्वयन सुचारु रूप से वर्ष 2020 से प्रारंभ हुआ।

दुग्ध उत्पादकों की मांग पर फैट के भाव में 20 रु. प्रति किलो की हुई वृद्धि

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विजन अनुरूप प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों की उन्नति, आय में वृद्धि, प्रदेश में नई श्वेत क्रान्ति लाने, उच्च नस्ल के पशुओं की उपलब्धता बढ़ाने, दुग्ध उत्पादन की लाभप्रदता की वृद्धि, डेयरी टेक्नोलॉजी उच्च कौशल प्राप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता और डेयरी टेक्नोलॉजी में आधुनिकता लाने के लिये शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिये उज्जैन में प्रदेश का पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज स्थापित किये जाने के प्रस्ताव का सर्व-सम्मति से अनुमोदन दुग्ध संघ की वार्षिक साधारण सभा में किया गया।

प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर दुग्ध सहकारी समिति स्थापित की जायेगी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की दूरदर्शी योजना के तहत डेयरी उत्पादन में आधुनिक तकनीक का प्रयोग, मशीनीकरण व उच्च स्तरीय मानव संसाधन प्रबंधन किया जा रहा है। दुग्ध संघ समितियों एवं दुग्ध उत्पादक किसानों के कल्याण, आय में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, दुग्ध संकलन को दोगुना करना, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर दुग्ध सहकारी समिति स्थापित करने के लिये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और मध्यप्रदेश दुग्ध फेडरेशन के समझौते का उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अनुमोदन किया गया।

उज्जैन दुग्ध संघ की 43वीं वार्षिक साधारण सभा में दुग्ध समितियों एवं दुग्ध उत्पादकों की प्रमुख मांग दूध के प्रति किलो फैट के भाव में वृद्धि किये जाने की मांग को पूरा करते हुए 20 रुपये प्रति किलो फैट की वृद्धि की गई। वृद्धि के बाद नये भाव 740 रुपये प्रति किलो फैट होंगे।

संभागायुक्त एवं प्रशासक दुग्ध संघ श्री गुप्ता ने कहा कि उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा उच्च गुणवत्ता का दूध एवं दुग्ध के उत्पाद के निरन्तर उपलब्ध कराने पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा दुग्ध संघ को सर्वोच्च श्रेणी 'ए+' प्रदान की गई है। इसी क्रम में इंडियन डेयरी एसोसिएशन पश्चिम क्षेत्र द्वारा नागपुर में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस में केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के द्वारा उज्जैन दुग्ध संघ को बेस्ट डेयरी प्लांट की श्रेणी में अवार्ड प्रदान किया गया है। उक्त उपलब्धियों के लिये संभागायुक्त श्री गुप्ता ने सभी सदस्य महानुभावों को शुभकामनाएं दी।

हर्षोल्लास से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा विशेष कार्यक्रम

भोपाल। मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पल को खास व यादगार बनाने के लिये शहरभर में विभिन्न सांस्कृतिक, रोमांचक व मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गई। पर्यटन दिवस की शुरुआत वोट क्लब पर योग, जुंबा और साइक्लोथन से हुई। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने 'पर्यटन और शांति' की थीम पर आधारित कई रोमांचक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। योग, जुम्बा और साइक्लोथॉन जैसी गतिविधियों के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने और पर्यटन के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया। सुबह 6 बजे से 300 से अधिक लोगों ने योग और जुंबा सत्र में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लाभ लेने के साथ मजेदार डांस फॉर्म के माध्यम से मनोरंजन किया और एक-दूसरे के साथ मेल-जोल भी बढ़ाया।

सुबह 8 बजे बोर्ड क्लब से साइक्लोथॉन में 500 से अधिक लोगों ने साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और साथ ही शहर के विभिन्न स्थलों को देखा। इसके अलावा गोल घर में चित्रकला, रंगोली, पुष्प सजाबट व मेहंदी प्रतियोगिता हुई।

कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर (मिंटो हॉल) में दोपहर को इस प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम घोषित किये गए। जिसके बाद भोपाल विविधा अकादमी ने गणेश वंदना व अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। समापन अवसर पर पर्यटन एवं शांति संदेश देने के लिये सफेद एवं नीले गुब्बारें आसमान में छोड़े गए।

सहकारी समितियों की पहुँच पूरे प्रदेश में हो- मंत्री श्री सारंग

मंत्री श्री सारंग की अध्यक्षता में बीज संघ का वार्षिक साधारण सम्मिलन

भोपाल : सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि सहकारी समितियों की पहुँच पूरे प्रदेश में हो, इसकी व्यापकता की जरूरत है। साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि समितियों के माध्यम से किसानों को जागरूक भी किया जायें कि वह किस तरह की फसल उगाये। संवाद के माध्यम से ही किसानों के हित में काम किया जा सकता है, इसके लिये समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मंत्री श्री सारंग बुधवार को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्यादित के 19वें वार्षिक साधारण सम्मिलन को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। बिना किसी ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाना, खाद और बीज की आपूर्ति, हर खेत में पानी पहुँचाने तथा खेत में फसल के उचित दाम मिल सके, इसके लिये सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि किसान की खेती को उत्कृष्ट करने के लिये उत्कृष्ट बीज की आवश्यकता है और इसलिये यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि समितियों के माध्यम से उचित और उत्कृष्ट बीज मिल सके। इसके लिये बीज संघ काम कर रहा है।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि बिना सहकार नहीं उद्धार और बिना संस्कार नहीं सहकार। इसके लिये पूरे संस्कार के साथ अपनी जो भी जिम्मेदारी है उसको निर्ववहन करें। उन्होंने कहा कि सरकार भी उत्कृष्ट एवं उन्नत तकनीक के माध्यम से और अग्रसर करने का प्रयास कर रही है। इसके लिये बहुत जल्द ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर रहे है। इसमें नई तकनीक को जोड़कर उत्कृष्टता की और लेकर जायेंगे। कृषि में अनुसंधान और तकनीक का बहुत महत्व है। आज कृषि में उन्नतता के लिये तकनीकों का उपयोग हो रहा है, इसको सोसायटी तक पहुँचाना बीज संघ की जिम्मेदारी है। इसके लिये भी प्रशिक्षण कार्यक्रम बना रहे है। इसके माध्यम से सही गुणवत्ता के बीज का उत्पादन हो सके, इसकी जानकारी मिलेगी। बीज संघ और सोसायटी के माध्यम से किसानों की खेती और उत्कृष्ट हो सके इस पर भी काम कर रहे है और संवाद के माध्यम से हर कठिनाईयों को दूर किया जायेगा।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि किसानों की उत्कृष्ट बीज और बीज के माध्यम से उत्कृष्ट फसल मिल सके। उन्होंने प्रदेश के संस्थागत बीज उत्पादन में बीज संघ के 77 प्रतिशत योगदान के लिये सभी सदस्य बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं को बधाई दी। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि कोई सुझाव हो तो लिखित में दें। साथ ही समस्यों का भी निराकरण करने की कोशिश की जायेगी। प्रादेशिक संघ ने कहा कि निष्क्रिय संस्था को भी सक्रिय किया जायेगा।

बैठक में बीज संघ के आगामी वर्ष की बीज उत्पादन संबंधी कार्ययोजना, वर्ष 2022-23 के अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वर्ष 2023-24 में अनअंकेक्षित वित्तीय पत्रकों, वर्ष 2023-24 के वास्तविक आय-व्यय एवं वर्ष 2025-26 के लिये प्रस्तावित बजट का भी अनुमोदन किया गया।

वार्षिक साधारण सभा में प्रदेश के विभिन्न जिलों की प्राथमिक बीज उत्पादक समितियों के प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल, पंजीयक सहकारी संस्थाएँ श्री मनोज कुमार सरियाम, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक श्री मनोज गुप्ता, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्री मनोज कुमार सिन्हा उपस्थित थे। प्रबंध संचालक बीज संघ श्री ए.के. सिंह द्वारा साधारण सभा के समक्ष विषयवार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन का पंजीयन हुआ प्रारंभ

किसान निर्धारित समय पर करायें पंजीयन : खाद्य मंत्री श्री राजपूत

किसान मोबाइल से घर बैठे कर सकते है पंजीयन

भोपाल : खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिये पंजीयन 19 सितम्बर से शुरू हो चुका है। किसान 19 सितम्बर से 4 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि किसान मोबाइल से घर से ही पंजीयन करा सकते है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि निर्धारित समय में पंजीयन करा लें, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो।

पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था

किसानों के लिये मोबाईल से पंजीयन करने की सुविधा के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की गई हैं। पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र

पर तथा एम.पी. किसान एप पर भी की गई है।

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है। इन केन्द्रों पर पंजीयन के लिये शुल्क राशि प्राप्त करने के संबंध में कलेक्टर निर्देश जारी करेंगे। प्रति पंजीयन के लिये 50 रूपये से अधिक शुल्क निर्धारित नहीं किया जाएगा। किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज़ एवं किसान के आधार कार्ड एवं अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा।

सिकमी/बटाईदार/कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।

आधार नंबर का वेरिफिकेशन

पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त OTP से या बायोमेट्रिक डिवाईस से किया जा सकेगा। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा।

किसानों को करें एसएमएस

विगत रबी एवं खरीफ के पंजीयन में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें एसएमएस से सूचित करने के निर्देश दिये गये हैं। गांव में डोंडी पिटवाकर ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर पंजीयन सूचना प्रदर्शित कराने तथा समिति/ मंडी स्तर पर बैनर लगवाने के निर्देश भी दिये गये हैं। किसान पंजीयन की सभी प्रक्रियाएँ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये हैं।

प्रदेश में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के लिए किए जाएंगे विशेष प्रयास - मुख्यमंत्री डॉ. यादव

दुग्ध उत्पादों का विकास कर प्रदेश को नंबर वन बनाएंगे

सांची ब्रान्ड को और सशक्त बनाया जाएगा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव इंदौर में सांची दुग्ध प्लांट में आयोजित कर्मचारी संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल

सांची दुग्ध संघ प्लांट का किया निरीक्षण

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सांची दुग्ध संघ एवं कर्मचारियों को समितियों के माध्यम से सशक्त करते हुए प्रदेश में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। सांची दुग्ध संघ के किसी भी कर्मचारी अथवा आउटसोर्स कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। प्रदेश में वर्तमान दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने के लिये विशेष प्रयास किये जाएंगे। सांची ब्रान्ड को और सशक्त बनाया जाएगा। शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. यादव इंदौर में मांगलिया स्थित सांची दुग्ध प्लांट में आयोजित कर्मचारी संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सांची दुग्ध संघ के प्लांट का निरीक्षण भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण प्रेम से गोपाल कहलाए। उन्होंने गौमाता के प्रति प्रेम के कारण जीवन भर गोपाल कहलाने में आनंद महसूस किया। उन्होंने अपने मुकुट पर मोर पंख को स्थान दिया। भगवान श्रीकृष्ण ने गौमाता को सदैव महत्व दिया। उन्होंने पशुपालन से जुड़कर आय के साधन के साथ-साथ जीवन अमृत (दुग्ध) से जुड़ने का संकेत दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार हर वर्ग के विकास के लिए विशेष प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 51 हजार से अधिक गांव हैं। बावजूद इसके दुग्ध उत्पादन में हम अन्य प्रदेशों के मुकाबले पीछे हैं। मध्यप्रदेश को दूध उत्पादन एवं उससे निर्मित होने वाले उत्पादों का विकास कर दुग्ध उत्पादन में नंबर वन बनाएंगे। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और इनसे जुड़ी सहकारी समितियों को सशक्त किया जाएगा। सांची दुग्ध संघ के किसी भी कर्मचारी को वीआरएस नहीं लेना पड़ेगा तथा आउटसोर्स के किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला जायेगा। दुग्ध संघ को सशक्त बनाने के लिए इन कर्मचारियों को इसका सहभागी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाते हुए इसके टर्न ओवर में बढ़ोत्तरी के लिये भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में दूध खरीदी पर पशुपालकों को बोनस दिया जाएगा।

दुग्ध संघ की वर्तमान समितियों की क्षमता का विकास करेंगे तथा प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के साथ साँची दुग्ध और उसके उत्पादों की खपत को बढ़ाने के लिये विशेष प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट से एमओयू किया गया है। सहकारिता के माध्यम से सांची ब्रान्ड को और सशक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा मध्यप्रदेश में कृषि विकास दर 25 प्रतिशत हुई है। पशुपालन को और अधिक बढ़ावा देने के लिये नई योजना में 10 से ज्यादा गायों का पालन करने वाले पशुपालकों को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन पर अनुदान का लाभ देंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा प्रदेश में बूढ़े पशुधन के संरक्षण के लिये उन्हें गौ-शालाओं में रखा जा रहा है। गौ-शालाओं का अनुदान भी बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों के दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी हेतु विशेष सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दुग्ध संघ के कर्मचारियों से संवाद किया तथा उन्हें हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को साँची दुग्ध संघ की ओर से प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया।

कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, राज्यसभा सांसद श्रीमती कविता पाटीदार, सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायकगण श्रीमती मालिनी गौड़, श्री मधु वर्मा, श्री मनोज पटेल तथा श्री गोलू शुक्ला, श्री गौरव रणदिवे, दुग्ध संघ अध्यक्ष श्री मोती सिंह पटेल, दुग्ध संघ कर्मचारी एवं गणमान्य जन उपस्थित थे। सांची दुग्ध संघ के एम.डी. डॉ. सतीश कुमार एस. ने दुग्ध संघ के कार्यों की जानकारी दी।

खाद-बीज की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

खाद-बीज की उपलब्धता और वितरण की समीक्षा

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में खाद-बीज की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जो कालाबाजारी करते पाया जाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाई सुनिश्चित की जाए। रबी सीजन में किसानों को खाद-बीज की कमी नहीं रहे। इसके लिए अभी से ही खाद-बीज के भण्डारण और आपूर्ति करने की व्यवस्था की जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में खाद-बीज की उपलब्धता और वितरण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मोहम्मद सुलेमान तथा अपर मुख्य सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री अशोक वर्णवाल तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर कृषि विकास अधिकारियों को 15 अक्टूबर तक प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फसलों के बोने के क्षेत्र चिन्हित कर आवश्यकतानुरूप खाद-बीज की व्यवस्था करें। अक्टूबर-नवम्बर माह में खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे, जिससे किसानों को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि जन-प्रतिनिधियों एवं जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से खाद-बीज की उपलब्धता के संबंध में चर्चा की जाएगी।

मुख्यमंत्री के प्रयास से डीएपी का आवंटन बढ़ा

बैठक में जाकनारी दी गई कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रयासों से भारत सरकार द्वारा डीएपी का आवंटन बढाकर 8 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है, जबकि रबी 2024-25 के लिए 6 लाख मीट्रिक टन डीएपी के आवंटन की सहमति दी गई थी। डीएपी के स्थान पर एनपीके के उपयोग के लिए जिलों को निर्देश जारी किए गए, जिससे खरीफ 2024 में डीएपी की कमी परिलक्षित नहीं हुई। डीएपी की कमी की पूर्ति के लिए प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में यूरिया एवं एसएसपी उपलब्ध है।

जनजाति संस्कृति एवं कला को संरक्षित रखने कलाकारों का योगदान महत्वपूर्ण : राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु
राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने हस्तशिल्पियों एवं जनजाति कारीगरों से की रू-ब-रू चर्चा

हस्तशिल्पियों एवं जनजाति कलाकारों की कला को राष्ट्रपति ने सराहा

भोपाल : राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने इंदौर प्रवास के दौरान मृगनयनी एंपोरियम में बुनकरों द्वारा हाथकरघा पर तैयार की गई रेशम एवं कॉटन की चंदेरी, महेश्वरी साड़ियों को देखा। इस दौरान उन्होंने जनजातीय क्षेत्र के हस्तशिल्पी, बुनकरों एवं जनजाति कारीगरों से रूबरू चर्चा की और उनकी कला को सराहा। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु को कलाकारों ने अपने हाथों से निर्मित हस्तशिल्प भेंट भी किया। यह सभी कलाकार अपनी विधा में पारंगत हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इनकी एक अलग ही पहचान है। राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर सभी कलाकार बहुत उत्साहित थे और उनसे मिलकर बहुत खुश हुए कि उन्हें देश के सर्वोच्च पद पर आसीन श्रीमती मुर्मु से रु-ब-रु मिलने व चर्चा करने का अवसर मिला। इस अवसर पर राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तथा लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक एवं सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी उपस्थित थे।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने शिल्पकारों से चर्चा के दौरान कहा कि हमारी पुरानी संस्कृति एवं परम्परा को संजो कर संरक्षित रखने की जरूरत है। यहाँ के शिल्पकार इसमें अच्छा योगदान दे रहे हैं। इन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है, जिससे इन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने शिल्पकारों के आग्रह पर उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने धार जिले के कारीगर श्री मुबारिक खत्री से चर्चा के दौरान उनकी कला बाग प्रिन्ट के बारे में जानकारी ली और पूछा कि वे कब से यह काम कर रहे हैं। कारीगर मुबारिक खत्री ने बताया कि उनकी 11 पीढ़ियों से बाग प्रिंट का कार्य किया जा रहा है। वे अपनी इस कला को आने वाली पीढ़ियों को भी सिखा रहे हैं। उन्होंने कॉटन के कपड़े पर बाग प्रिंट कैसे किया जा सकता है, यह करके भी दिखाया। उन्होंने बताया कि अब बांस एवं सिल्क की साड़ियों पर भी बाग प्रिंट किया जाता है।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु को खरगोन जिले के महेश्वर के बुनकर श्री अलाउद्दीन अंसारी ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हथकरघा साड़ी के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि नर्मदा नदी में दोपहर के समय सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं और उनसे नदी में जो लहरें चमकती हैं, उन्हीं लहरों का प्रिंट हथकरघा साड़ियों की बॉर्डर पर उतारा जाता है। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु इस कलाकारी से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने पूछा कि वे यह काम कब से कर रहे हैं। श्री अंसारी ने बताया कि उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी यह कार्य कर रहा है। वर्तमान समय में वे अपने इस कार्य से 300 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जिसमें 70 महिलाएं शामिल हैं।

वर्तमान में भोपाल निवासी एवं मूलत: डिंडोरी की निवासी गोंड भित्तिचित्र की कलाकार पदमश्री श्रीमती दुर्गाबाई श्याम की कला को देखकर राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु बहुत प्रभावित हुई और सराहना की। उन्होंने कहा दुर्गाबाई संस्कृति एवं कला को जीवित रखने और उसे आगे बढ़ाने के लिये कार्य कर रही हैं। पद्मश्री दुर्गा बाई ने बताया कि वे बच्चों को इस कला को सीखा रही है और एक संस्था के माध्यम से अन्य लोगों को भी नि: शुल्क इस कला का प्रशिक्षण दे रही है।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने झाबुआ जिले के कलाकार दंपत्ति पदमश्री श्री रमेश एवं श्रीमती शांति परमार द्वारा निर्मित "झाबुआ डॉल्स" को देखकर पूछा कि क्या यह गुड़िया मिट्टी से बनाई गई है। कलाकारों ने बताया कि उनके द्वारा कपास एवं कपड़े से आकर्षक गुड़ियों का निर्माण किया जाता है। वे अपनी इस कला को जीवित रखने के लिये अन्य लोगों को भी नि:शुल्क प्रशिक्षण देते हैं। उन्होंने बताया कि बाजार और मेलों में वे जितनी गुड़िया लेकर जाते हैं, वे सभी बिक जाती हैं। राष्ट्रपति ने खरीदी साड़ी और यूपीआई से किया डिजिटल पेमेंट राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने मृगनयनी एंपोरियम में हथकरघा पर निर्मित साड़ियों को देखा और उनकी कलाकारी देखकर प्रसन्न हुई। वहां कार्यरत महिला कर्मचारियों से उन्होंने साड़ियों के नाम एवं पैटर्न की जानकारी ली। इस पर उन्हें चंदेरी, महेश्वरी, कॉटन एवं सिल्क की साड़ियां दिखायी गई और उनके बारे में विस्तार से बताया गया। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने वहां की महिला कर्मचारियों से अपनी पसंद की हल्के रंग की एक साड़ी उनके लिये चुनने का अनुरोध किया। इस पर सरिता गव्हाड़े ने राष्ट्रपति के लिए हल्के पिंक रंग की महेश्वरी साड़ी पसंद कर दी। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने इस साड़ी का काउंटर पर जाकर यूपीआई से डिजिटल भुगतान भी किया। काउंटर के कर्मचारी कविता भिलवारे एवं विपुल सिंह द्वारा डिजिटल पेमेंट जमा कराया गया। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु को महिला कर्मचारी अरूणा रापोतू, साधना शुक्ला, संगीता शुक्ला, मीना चौरसिया एवं वंदना कोठारी द्वारा साड़ियां एवं सिल्क के कपड़े दिखाये गये।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भेंट की चंदेरी साड़ी राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु के मृगनयनी एम्पोरियम इंदौर में हस्तशिल्प कलाकारों से संवाद एवं उनकी कला के अवलोकन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भी प्रदेश की ओर से राष्ट्रपति को चंदेरी साड़ी भेंट की।

मंत्री श्री सारंग करेंगे 'स्वच्छता का संकल्प' अभियान और 'सेवा से सीखे' कार्यक्रम की शुरुआत सहकारिता विभाग और खेल एवं युवा कल्याण विभाग में " स्वच्छता ही सेवा" पखवाड़ा में होंगे विभिन्न कार्यक्रम

भोपाल: खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग के मार्गदर्शन में "स्वच्छता ही सेवा" कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक खेल विभाग के सभी परिसरों में 'स्वच्छता के संकल्प' के साथ वृहद स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। मंत्री श्री सारंग इसकी शुरुआत मंगलवार 17 सितंबर को सुबह 9 बजे वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी, बोट क्लब से करेंगे। इसी प्रकार टी. टी. नगर खेल स्टेडियम में दोपहर 12 बजे से 'सेवा से सीखे खिलाड़ियों द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन और वृद्ध-जनों की सेवा का आयोजन भी किया गया है।

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान सहकारिता और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत स्वच्छता सेवा एवं युवाओं से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। सहकारिता विभाग अंतर्गत सभी संस्थाओं एवं सहकारी समितियां में भी इस दौरान वृहद् स्तर पर स्वच्छता से सेवा अभियान चलाया जाएगा। मंत्री श्री सारंग विभागीय स्वच्छता से सेवा अभियान अंतर्गत सहकारी संस्थाओं एवं समितियाँ में चलने वाले इस अभियान में शामिल होंगे।

उल्लेखनीय है कि गत दिनों खेल एवं युवा कल्याण तथा सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित 'स्वच्छता ही सेवा 2024' में खेल एवं युवा कल्याण और सहकारिता विभाग की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देशानुसार खेल एवं सहकारिता विभाग इस पखवाड़े में विभिन्न गतिविधियां आयोजित करेंगे। परिसरों की स्वच्छता के साथ वृद्ध जनों की सेवा, ब्लड डोनेशन कैंप, सेवा से सीखे कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं में

सेवा की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन अभियान को और अधिक गति देने इस वर्ष "स्वच्छता ही सेवा" 2024 पखवाड़ा 'स्वभाव स्वच्छता-संस्कार स्वच्छता' थीम के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश इस अभियान को पूरी प्रतिबद्धता के साथ सफल बनाने में कार्य कर रहा है।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग की सहभागिता से कम से कम तीन कार्यक्रम इसमें शामिल किए जायेंगे। अभियान अवधि के प्रत्येक दिन यूथ को-ऑर्डिनेटर के साथ मिलकर गतिविधियां संचालित की जायेगी। जन - प्रतिनिधियों एवं नागरिकों के सहयोग से जिला स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। विभिन्न अभियानों एवं गतिविधियों के माध्यम से बड़े स्तर पर जन-जागरूकता एवं नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। खेल परिसर में स्वच्छता से लेकर पौध-रोपण तक विभिन्न गतिविधियां की जायेगी।

(पृष्ठ 1 का शेष)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों.....

उन्होंने कहा कि ऐसा होते ही पूरे देश में सहकारिता की पहुँच हो सकेगी, जिससे तहसील और जिले की संस्थाएं बनेंगी और राज्य की संस्थाओं को भी नई ताकत और गति मिलेगी।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि पुराने समय में बने PACS बंद हो गए, लेकिन अब जो नए PACS रजिस्टर होंगे वह बंद नहीं होंगे, क्योंकि हमने PACS को 25 अलग-अलग तरह के कामों से जोड़कर इन्हें viable बनाया गया है। उन्होंने कहा कि PACS पहले कृषि के लिए शॉर्ट टर्म लोन देने का काम करते थे, लेकिन अब PACS को डेयरी, मत्स्य, गोदाम, सस्ते अनाज की दुकान, सस्ती दवाइयों की दुकान, पेट्रोल पंप, एलपीजी सिलिंडर, पानी के वितरण जैसी चीजों से जोड़ा गया है। इससे हर पंचायत में बनने वाले PACS हमारे त्रिस्तरीय सहकारी ढांचे को मजबूती देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जब PACS मजबूत होता है, PACS की संख्या बढ़ती है तो जिला सहकारी बैंक अपने आप मजबूत होते हैं, और जिला सहकारी बैंक मजबूत होने से राज्य सहकारी बैंक मजबूत होते हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज श्वेत क्रांति 2.0 के SoP का विमोचन किया गया है। उन्होंने कहा कि श्वेत क्रांति 2.0 महिला स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण का काम करेगा। उन्होंने कहा कि दूध के उत्पादन और ख़ास कर सहकारी डेयरियों के साथ माताएं-बहनें जुड़ी हुई हैं। माताओं-बहनों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का काम डेयरी क्षेत्र जितना और कोई नहीं कर सकता। श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में 36 लाख बहनें डेयरी क्षेत्र से जुड़कर रु. 60,000 करोड़ का व्यापार करती हैं। उन्होंने कहा कि अमूल आज पूरे विश्व में खाद्य क्षेत्र में सबसे विश्वसनीय ब्रांड बन गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से श्वेत क्रांति 2.0 महिला सशक्तिकरण करेगा, उसी तरह श्वेत क्रांति 2.0 कुपोषण के खिलाफ जंग को भी ताकत देगा। जब दूध की उपलब्धता बढ़ेगी तो उसका सबसे बड़ा फायदा गरीब और कुपोषित बच्चों को होगा। गुजरात का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मां का स्वभाव है कि अगर घर में पशुपालन हो रहा है और मां डेयरी के साथ जुड़ी है तो वह अपने बच्चे को निश्चित रूप से पहले कुपोषण से मुक्त करने का काम करेगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार कितने भी साल प्रयास करे, जब तक मां प्रयास नहीं करे, बच्चे को कुपोषण से नहीं निकाल सकते।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि हमारे घरों में माताएं और बहनें बहुत सारा काम करती हैं, लेकिन इसके बावजूद औपचारिक रोजगार कि दृष्टि से बेरोजगार मानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि श्वेत क्रांति 2.0 ख़ास कर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार देने का काम करेगा। जब महिलाओं के नाम पर बैंक चेक आएगा तो उन्हें बहुत ख़ुशी मिलेगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के संकल्प को पशुपालन के व्यवसाय से और मजबूत होगी।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि कृषि योग्य भूमि की उर्वरता बढ़ाने का काम भी पशुपालन के माध्यम से ही होगा। उन्होंने कहा कि इन उद्देश्यों को एक साथ समाहित करते हुए श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि कई लोगों को आशंका है कि इस कार्यक्रम के लिए बजट सहायता मिलेगी कि नहीं, इसलिए पशुपालन विभाग को आश्वस्त करता हूँ कि यह सरकार की सर्वाधिक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है और इस कार्यक्रम को पूरा बजट मिलेगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि एक महत्त्वपूर्ण पहल 'सहकारिता में सहकार' के रूप में की गई है। उन्होंने कहा कि इसके तहत हमने गुजरात के दो जिलों पंचमहाल और बनासकांठा में प्रयोग किए। हमने सहकारिता क्षेत्र की सभी संस्थाओं के बैंक अकाउंट सहकारिता बैंक में खोलने का फैसला किया। इसके अलावा प्राथमिक सहकारी समिति और दुग्ध उत्पादक समिति के साथ जुड़ी माताओं बहनों को एक डेबिट और क्रेडिट कार्ड दिया, जिससे वे वित्तीय रूप से मजबूत हुईं। इसके तहत अब तक चार लाख से ज्यादा बैंक अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में खोलने का काम हुआ है और सिर्फ दो जिलों में 550 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा हुई। 1732 माइक्रो एटीएम खुले और 20,000 नए क्रेडिट कार्ड देने का काम हुआ। लगभग 24 लाख के डिजिटल ट्रांजेक्शन नए क्रेडिट कार्ड से हुए। उन्होंने कहा कि अब तक गुजरात में पूरी तरह इसे लागू नहीं किया गया है, लेकिन 9 लाख से अधिक अकाउंट अब तक खुले हैं और करीब 4000 करोड़ रुपए का डिपोजिट कोऑपरेटिव बैंकों में बढ़ा है। इसके तहत कुल 2600 माइक्रो एटीएम बांट दिए गए हैं। अब हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि हमने सुगमता के लिए तय किया है इस कार्यक्रम के लिए जिले को यूनिट बनाएंगे। जिस जिले में सहकारिता का व्यापार अच्छा है, उन जिलों में 'सहकारिता में सहकार' के कांसेप्ट को लॉन्च करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में किसी जिले या तहसील पर आप अंगुली रख दें, आपको सहकारी समितियां नज़र आया जायेंगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के पास पूरे देश की हर पंचायत, हर तहसील, हर जिले और हर राज्य का डेटाबेस है, और साथ ही पूरे राष्ट्र का डेटाबेस है। इससे पता लगाया जा सकता है कि सहकारी समितियां कितनी है, किस प्रकार की है, उसका ऑडिट वर्क कैसा है। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव डेटाबेस को हमने राज्य सहकारी रजिस्टर और जिलों के सहकारी रजिस्टर और हर जिला कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच में उपलब्ध करा दिया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) नई डेयरियां खोलने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि एक वैज्ञानिक आयोजन हमने किया है और इसके लिए सभी प्रकार की एजेंसियां एक साथ मिलकर काम कर रही हैं।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि श्वेत क्रांति के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया में एक सितारा बनकर उभरा है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बन चुका है। पशु चारा, बीज, कृत्रिम गर्भाधान, गोबर से आर्थिक स्थिति में सुधार और पशुओं के स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि इसे और भी मजबूत कर डेयरी के जरिये अब विदेशी मुद्रा का अर्जन भी किया जा सकेगा। हम हमारे प्रोडक्ट को विश्व के बाजार में एक्सपोर्ट भी करेंगे और इसके लिए टेस्टिंग उपकरण, बल्क में मिल्क कलेक्शन और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए 38 उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन के लिए भी भारत सरकार ने एक वैज्ञानिक आयोजन किया है जो आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने रखेंगे। डेयरी से जुड़ी कोई भी मशीनरी अब हमें नीदरलैंड से या जापान से लाने की जरूरत नहीं है। इनका शत प्रतिशत उत्पादन भारत में होगा। एक प्रकार से डेयरी क्षेत्र में हम संपूर्ण आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़े हैं।

समर्थन मूल्य पर उपार्जन कार्य में उपयोगी नाप-तौल उपकरणों का होगा सत्यापन

खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने दिये निर्देश

भोपाल : खरीफ उपार्जन वर्ष 2024 -25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जन शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। अभी किसानों द्वारा रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपार्जन केन्द्रों से संबंधित समितियां एवं कृषि उपज मंडी समितियों के नाप-तौल यंत्रों का शत- प्रतिशत सत्यापन उपार्जन कर शुरू होने के पूर्व कराया जाए। साथ ही जिले में उत्पादन कार्य में संलग्न शासकीय, निजी अथवा संयुक्त भागीदारी के भंडार गृहों के धर्म कांटा की भी जांच और सत्यापन सुनिश्चित करें। साथ ही इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट भी भेजें।

ग्रामीणों को सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी : वन मंत्री श्री रावत

60 लाख रुपये लागत की 3 सड़कों का भूमि-पूजन

वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री रामनिवास रावत ने श्योपुर जिले के अनुसूचित जनजाति विकासखण्ड कराहल क्षेत्र में 60 लाख रुपये की लागत से बनने वाली 3 मुरम सड़कों का भूमि-पूजन किया। श्री रावत ने कहा कि ग्रामीणों को सड़कों के निर्माण से सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। सड़कों के निर्माण से क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने बताया है कि इन सड़कों की माँग ग्रामीणों द्वारा लम्बे समय से की जा रही थी। इन सड़कों का निर्माण तेन्दूपत्ता मद से अधोसंरचना विकास कार्य के अंतर्गत वन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

इन सड़कों का हुआ भूमि-पूजन

ग्राम मेहरवानी से कराहल सड़क लम्बाई साढ़े 6 किलोमीटर, लागत 19.82 लाख, रानीपुरा से दांती सड़क लम्बाई 10 किलोमीटर, लागत 19.50 और दांती से पहेला सड़क लम्बाई 8 किलोमीटर, लागत 19.91 का भूमि-पूजन किया गया।

भूमि-पूजन कार्यक्रम में सीसीएफ ग्वालियर श्री टी.एस. सुलिया, डीएफओ श्री सी.एस. चौहान और जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल की आमसभा श्री मनोज कुमार सरियाम, प्राधिकृत अधिकारी एवं पंजीयक, सहकारी संस्था की अध्यक्षता में सम्पन्न

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ के 53 वें वार्षिक साधारण सम्मिलन के अवसर पर संघ की समस्त सदस्य संस्थाओं के सम्माननीय प्रतिनिधि गणों का मैं हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ व्दारा अपने सीमित संसाधनों एवं न्यूनतम मानव संसाधन के साथ वर्ष 2023-24 में अपने उद्देश्यों के अनुरूप विभिन्न विषयक प्रशिक्षण एवं नवाचार किए जाने के प्रयास किये गये हैं-

वर्ष 2023-24 के महत्वपूर्ण कार्य

1. राज्य सहकारी संघ द्वारा आठ नई संस्थाओं को सदस्यता प्रदान की गई। सदस्य संख्या 166 थी जो वर्तमान में बढ़कर 174 हो गई हैं।

2. सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन, शिक्षा प्रशिक्षण योजनाअंतर्गत 45,533 को प्रशिक्षण प्रदाय।

3. पैक्स कम्प्यूटराइजेशन पर 2898 को प्रशिक्षण प्रदाय।

4. सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम आनलाइन (एच. डी.सी.एम) 20 सप्ताह के दो सत्र कम्प्यूटर संबंधी पी. जी. डी. सी.ए एवं डी. सी.ए पाठ्यक्रमों का संचालन।

5. संघ द्वारा न केवल प्रदेश के बल्कि बिहार सहकारिता विभाग के 50 प्रसार अधिकारियों हेतु तीन माह का एच. डी. सी. एम प्रशिक्षण आयोजित।

6. सहकारी संस्थाओं एवं अन्य विभागों को आउटसोर्स के रूप में दक्ष एवं तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत एजेंसी के रूपमें 2100 मानव संसाधन उपलब्ध कराए गए।

7. नौगांव प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण कार्य प्रारंभ।

8. संघ व्दारा हस्तशिल्प क्षेत्र में कारीगरों को सहकारिता के आधार पर संगठित कर उनके कौशल उन्नयन एवं आय संवर्धन हेतु विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय नई दिल्ली को प्रोजेक्ट प्रस्तुतकर CHCDS परियोजना प्रारंभ की गई। योजनान्तर्गत 650 को प्रशिक्षित किया गया। 565 को टूलकिटका वितरण किया गया। तीन सी एफ सी एवं एक एम्पोरिया का निर्माण प्रारंभ।

9. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग के हितग्राहियों के कौशल उन्नयन एवं आय संवर्धन हेतु PM दक्ष योजना के संचालन हेतु भारत सरकार सामाजिक न्याय विभाग व्दारा संघ को मान्यता प्रदान की गई है। योजनान्तर्गत 1200 को प्रशिक्षित किया गया

10.भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय की अपेक्षा अनुरूप बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं हेतु नवीन उपविधि का प्रकाशन किया गया।

वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित कार्यक्रम

1. शिक्षा प्रशिक्षण योजनाअंतर्गत 50900 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित। राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय सेमीनार तथा महिला एवं अन्य सहकारी संस्थाओं के संचालकों हेतु 3-3 दिवस के नेतृत्व विकास प्रशिक्षणों का आयोजन।

2. एच. डी. सी. एम. आनलाईन तथा PGDC, DCA प्रशिक्षण के सत्रों का संचालन।

3. नवीन क्षेत्रों में सहकारी समितियां बनाए जाने हेतु कार्य शाला का आयोजन एवं नये क्षेत्रों में सहकारिता के विस्तार हेतु नये सेक्टरों से संबंधित आदर्श उपविधियो का निर्माण।

4. नवाचार समितियों का संघ बनाया जाना।

5. सहकारी विश्वविद्यालय बनाए जाने हेतु कार्यवाही।

6. सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव में म.प्र. गृहनिर्माणमण्डल के माध्यम से कार्यालय, अध्ययन कक्ष, बाउन्ड्रीवाल का निर्माण पूर्ण केन्द्र इंदौर में भी निर्माण कार्य प्रगति की ओर।

7. सहकारी संस्थाओं एवं अन्य विभागों को आउटसोर्स के रूप में दक्ष एवं तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत एजेंसी के रूप में अधिकाधिक मानव संसाधन उपलब्ध कराना। इस हेतु शासकीय भंडार कय नियम अंतर्गत संघ को मान्यता दिलाने संबंधी प्रस्ताव शासन को प्रेषित।

8. भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) नईदिल्ली के द्वारा वृहत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (CHCDS) अंतर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन।

9. PM दक्ष योजनान्तर्गतप्राप्तस्वीकृतिअनुसारप्रशिक्षणोंकाआयोजन।

10. पैक्स कम्प्यूटराईजेशन हेतु BIRD (NABARD) व्दारा निर्मित माड्यूल पर पैक्स कर्मियों हेतु प्रशिक्षण।

11. नौगांव प्रशिक्षण केन्द्र पर स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त कर पी. जी. डी.सी.ए., डी.सी.ए., ए.आई., सायबर सिक्योरिटी आदि डिप्लोमा कोर्स को प्रारंभ करना।

राज्य/जिला सहकारी संघ के प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (TOT) सम्पन्न

भोपाल। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में दिनांक 23 सितम्बर 2024 से 27 सितम्बर 2024 तक आयोजित कार्यक्रम में 33 प्रतिभागियों (म.प्र. राज्य सहकारी संघ के प्रशिक्षक/व्याख्याताओं / प्राचार्यो / अधिकारियों एवं जिला सहकारी संघों के प्रबंधकों) ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन एवं महाप्रबंधक श्री संजय सिंह द्वारा दीप प्रज्जवलन एवं मॉ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। प्रबंध संचालक द्वारा प्रशिक्षण पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम के प्रथम दिन दिनांक 23 सितम्बर 2024 को लेखांकन एवं अंकेक्षण पर श्री अभय गोखले, से.नि. प्रबंधक अपेक्स बैंक भोपाल द्वारा प्रतिभागियों को विस्तार से समझाया गया।

कार्यक्रम के द्वितीय दिन दिनांक 24 सितम्बर 2024 को राज्य संघ की वेबसाईट के बारे में श्री आशु तिवारी, प्रोपराईटर एटम्स ग्रुप, भोपाल द्वारा विस्तार से समझाया गया। नवाचार पर श्री तुमुल सिन्हा, अंकेक्षण अधिकारी द्वारा प्रदेश में नवाचार की समितियों एवं नवीन कार्यो से अवगत कराया गया। निर्वाचन पर श्री अविनाश सिंह, से.नि. वरि. सह. निरीक्षक द्वारा निर्वाचन की महत्वता एवं प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

तृतीय दिवस दिनांक 25 सितम्बर 2024 प्रभावी संप्रेषण कला एवं आमजन से संवाद एवं प्रशिक्षण में आने वाली चुनौतियों एवं निराकरण पर श्री राजेन्द्र सक्सेना, मोटीवेशनल स्पीकर, भोपाल, द्वारा विस्तार पूर्वक समझाया गया।

संचालक मण्डल के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व तथा सहकारी समितियों का प्रबंधन पर श्री श्रीकुमार जोशी, संयुक्त आयुक्त सहकारिता (से.नि.) द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। ऑनलाईन प्रशिक्षणों का आयोजन, पावर पाइन्ट प्रजेन्टेशन, वर्ड एवं एक्सल, जीपीटी इत्यादि पर श्री आनन्द पराड़कर, कम्प्यूटर फेकल्टी द्वारा विस्तृत चर्चा की गई। प्रतिभागियों के प्रश्नों का समाधान किया गया।

चतुर्थ दिवस दिनांक 26 सितम्बर 2024 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) व्दारा संचालित योजना की जानकारी श्री गौरव जादम, एन.सी.डी.सी., क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा दी गई।

म.प्र. की सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी एवं उत्कृष्ट अनुसंधान केन्द्र अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल का प्रतिभागियों को अध्ययन भ्रमण करवाया गया।

पंचम दिवस दिनांक 27 सितम्बर 2024 को श्रीमती सृष्टि उमेकर, मोटीवेशनल स्पीकर, भोपाल द्वारा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व, अच्छे प्रशिक्षक के गुण एवं विशेषताएं विषय पर विस्तार से समझाया गया।

कार्यक्रम समापान अवसर पर सभी प्रतिभागियों से प्रशिक्षण कार्यक्रम के फीडबैक लिये गये तथा श्री संजय सिंह, महाप्रबंधक के हस्ते प्रमाण पत्र वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन/सत्र समन्वयक श्रीमती मीनाक्षी बान, प्राचार्य द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में श्री धनराज सैंदाणे, श्री प्रवीण कुशवाह, श्री विक्रम मुजुमदार का विशेष सहयोग रहा।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।